



प्रेस विज्ञप्ति / Press Release

24 नवम्बर / November, 2020

भागीदार राज्यों में एमएसएमई पारितंत्र के सुदृढीकरण हेतु सिडबी द्वारा 7वें समझौता ज्ञापन का निष्पादन

SIDBI signs 7th MoU to strengthen MSME ecosystem in the partner States

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी); सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए कार्यरत प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसने तमिलनाडु राज्य में एमएसएमई पारितंत्र के विकास के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया है।

Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the principal financial institution engaged in the promotion, financing and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), has entered a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of Tamilnadu (GoTN) to develop the MSME ecosystem in the State.

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री थिरु एडापडुडी के. पलनीस्वामी, एवं थिरु पी. बेंजामिन माननीय मंत्री, एमएसएमई, तमिलनाडु सरकार की उपस्थिति में श्रीमती अनु जार्ज, आईएएस, उद्योग आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, तमिलनाडु सरकार और श्रीमती चित्रा आलै, क्षेत्रीय प्रमुख, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव थिरु के. षण्मुगम, आईएएस एवं प्रमुखा सचिव श्री डॉ. के. गोपाल, आईएएस भी उपस्थित रहे।

The MoU was signed by Smt. Anu George, IAS, Industries Commissioner and Director of Industries and Commerce, GoTN and Smt. Chitra Kartik Alai, Regional Head, SIDBI, Chennai in the presence of the Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu, Thiru Edappadi K. Palaniswami & Thiru P. Benjamin, Hon'ble Minister for MSME. On the occasion Thiru K. Shanmugam, IAS, Chief Secretary & Dr. K. Gopal, IAS, Principal Secretary were also present

इस समझौते के तहत सिडबी द्वारा तमिलनाडु सरकार के साथ एक परियोजना प्रबंध इकाई (पीएमयू) स्थापित की जाएगी। पीएमयू की भूमिका प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को डिजाइन करने की होगी जो कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा अधिकारों, अनुसंधान और विकास, एमएसएमई इकाईयों और प्रौद्योगिकी संचालित व्यवसायों / स्टार्ट-अप आदि के बीच व्यावसायिक क्षमताओं और सहयोग बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान / उसका लाभ उठाने जैसे क्षेत्रों में तमिलनाडु सरकार द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं। उक्त पीएमयू, राज्य में एमएसएमई इकाईयों को लक्षित

हस्तक्षेपों, पहलों, परियोजनाओं आदि की सुविधा प्रदान करेगा और उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने और अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से सुझाव देगी।

Under the MoU, SIDBI shall deploy a Project Management Unit (PMU) in Government of Tamilnadu. The role of the PMU will be to design training and capacity building programs, which may be taken up by GoTN, in areas such as technology transfer, promotion of innovation, intellectual property rights, research & development, leveraging of technology / technology solutions for enhancing business capabilities and collaborations between MSMEs & technology driven businesses / startups, etc. The PMU will facilitate interventions, initiatives, projects etc. for MSMEs in the State with the objective of enhancing efficacy and removal of bottlenecks.

इस अवसर पर सिडबी के उप प्रबंधक निदेशक श्री वी एस वी राव ने कहा कि “यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों के अनुरूप सिडबी ने राज्य सरकार के साथ निकट सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमबद्ध दृष्टिकोण अपनाया है। सिडबी ने सात राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा निकट भविष्य में 4 और राज्यों के साथ इसे योजित किया गया है। विशेषज्ञ टीम के साथ पीएमयू की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न स्वरूपों के बीच एक संकेन्द्रित जुड़ाव लाना है, जो हमें एक मजबूत एवं आत्मनिर्भर राज्य तथा देश की ओर अग्रसारित करे। पीएमयू की वजह से तमिलनाडु राज्य में वित्तीय और गैर-वित्तीय मोर्चों में गहरा तालमेल बनने की अपेक्षा है। सिडबी, राज्यों में क्लस्टर विकास के ढांचागत पहलुओं का समर्थन करने के लिए, एक क्लस्टर विकास निधि की संरचना भी कर रहा है।”

On this occasion Shri V S V Rao, DMD SIDBI, said, “In line with UK Sinha Committee recommendations SIDBI has adopted programmatic approach to foster closer cooperation with State government. SIDBI has signed MoU with seven states and 4 more are planned in near future. The setting up of PMU with expert team aims at bringing a focused engagement in various forms leading to a stronger Atmanirbhar state and country. The PMU is expected to bring a deeper engagement in financial and non-financial fronts in the State of Tamilnadu. SIDBI is also structuring a cluster development fund for supporting the infrastructural aspects of cluster development in States”

अपने निरंतर प्रयास के साथ, सिडबी अब तक विभिन्न 7 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों का निष्पादन कर चुका है। सिडबी के उप प्रबंध निदेशक श्री मनोज मित्तल द्वारा कल उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी और उत्तराखंड सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया। राज्य के उद्यमों पर लक्षित उत्प्रेरण के लिए चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के लिए एक नीति पत्र भी इस अवसर पर जारी किया गया।

With its continuous endeavor, SIDBI has so far entered into 7 MoUs with different states. Yesterday MoU was signed with the Government of Uttarakhand yesterday in presence of Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand, Shri Trivendra Singh Rawat, Shri Manoj Mittal, Deputy Managing Director, SIDBI and other dignitaries of Uttarakhand Government. A policy paper for medical devices sector was also released for targeted thrust at state enterprises.

5 भागीदार राज्यों में अब पीएमयू संस्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने अंतरालों के रूपांकन का काम शुरू किया है ताकि अन्य राज्यों में प्रचलित अच्छी प्रथाओं के साथ इनकी तुलना के साथ ये एमएसएमई

पारितंत्र के विकास और सुदृढीकरण के सूत्रधार के रूप में विकसित हों। ये पीएमयू - उद्यमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस आदि पर जोड़े जाने का समर्थन करेंगे।

In 5 partner states, PMUs have since been set up. They have commenced mapping of the gaps, match these with good practices in other states as also evolve as facilitators of development & strengthening of MSME eco system. They shall support onboarding onto digital platforms, stock exchange listing, e-commerce platforms such as Government e-Marketplace etc.

सिडबी, साझेदार राज्यों के बीच एक अग्रदूत के रूप में कार्य करके, एक ऐसे अधिक उत्तरदायी पारितंत्र के उद्भव में योगदान करना चाहता है जो स्थानीय (लोकल) के लिए मुखर रहते हुए और भारत के एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के संकल्प को पुष्ट करता है।

By acting as harbinger amongst partner States, SIDBI intends to contribute to emergence of more responsive ecosystem which is Vocal for Local and strengthens nation's resolve to emerge as Atma Nirbhar Bharat.

सिडबी के बारे में: 1990 में अपने गठन के बाद से सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न ऋण और विकासात्मक उपायों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) के जीवन को छुआ है, चाहे ये पारंपरिक व घरेलू छोटे उद्यमी हों; उद्यमिता पिरामिड के निम्नतम स्तर के उद्यमी हों अथवा उच्चतम स्तर के ज्ञान-आधारित उद्यमी हों। सिडबी 2.0 अपने साथ समावेशी, अभिनव और प्रभाव-उन्मुख संबद्धताओं की दृष्टि को लेकर चल रहा है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट <https://www.sidbi.in> पर जाएँ।

About SIDBI: Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements. SIDBI 2.0 carries the vision of inclusive, innovative and impact-oriented engagements.

To know more, check out: <https://www.sidbi.in>